भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

27.11.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 416 का उत्तर

राजमुंदरी में नई रेललाइन का सर्वेक्षण

416. श्रीमती दग्गुबाती पुरंदेश्वरी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में नई रेल लाइनों के लिए अनुमोदित सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है और विशेषकर राजमुंदरी लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जोन/खंड-वार तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इन सर्वेक्षणों के लिए आबंटित और व्यय की गई निधियों का जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेल मंत्रालय ने नई रेल-लाइनें बिछाने के लिए उन परियोजनाओं को मंजूरी दी है जिनके सर्वेक्षण पहले ही पूरे किए जा चुके हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो जोन/खंड-वार इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या नई रेल-लाइनें बिछाने के लिए पूर्ण सर्वेक्षण प्रतिवेदनों पर अंतिम निर्णय लेने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जिन परियोजनाओं के सर्वेक्षण पहले ही पूरे हो चुके हैं, उनमें तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

राजमुंदरी में नई रेललाइन के सर्वेक्षण के संबंध में दिनांक 27.11.2024 को लोक सभा में श्रीमती दग्गुबाती पुरंदेश्वरी के अतारांकित प्रश्न सं. 416 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ङ): नई रेल लाइन परियोजनाओं का सर्वेक्षण/स्वीकृति क्षेत्रीय रेल-वार की जाती है न कि संसदीय निर्वाचन राज्य-वार, क्षेत्र-वार क्योंकि रेलवे के सर्वेक्षण/परियोजनाएं राज्य/संघ शासित क्षेत्र/निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् वित्त वर्ष और वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 में, आंध्र-प्रदेश में पूर्णत:/आंशिक रूप से पड़ने वाले क्षेत्रों सहित देशभर में 25,575 किलोमीटर की कुल लंबाई वाले नई लाइनों जिसकी लागत 710 करोड़ रू. है, के लिए 287 सर्वेक्षण अनुमोदित किए गए हैं। पिछले 03 वर्षों के दौरान अर्थात् इन सर्वेक्षणों पर किया गया व्यय 167.47 करोड़ रूपए है।

इन अनुमोदित नई लाइनों के सर्वेक्षणों का क्षेत्रीय रेल-वार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	ज़ोन	अनुमोदित नई लाइन सर्वेक्षणों की सं.	कुल लंबाई (कि.मी. में)
1	मध्य रेलवे	15	1443
2	पूर्व तट रेलवे	26	1900
3	पूर्व मध्य रेलवे	20	1053
4	पूर्व रेलवे	5	171
5	उत्तर मध्य रेलवे	10	605
6	पूर्वोत्तर रेलवे	5	442
7	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	30	2865
8	उत्तर रेलवे	33	1485
9	उत्तर पश्चिम रेलवे	20	1709
10	दक्षिण मध्य रेलवे	25	4293
11	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	27	4045
12	दक्षिण पूर्व रेलवे	17	1335

13	दक्षिण रेलवे	6	907
14	दक्षिण पश्चिम रेलवे	16	1566
15	पश्चिम मध्य रेलवे	9	673
16	पश्चिम रेलवे	23	1083

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान स्वीकृत 34 नई लाइन परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

रेलवे	पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में स्वीकृत नई लाइन परियोजनाओं की सं.	कुल लंबाई (कि.मी. में)
मध्य	04	524
पूर्व तट	08	616
पूर्व मध्य	03	53
पूर्वोत्तर	02	82
उत्तर पश्चिम	08	278
दक्षिण मध्य	01	57
दक्षिण पूर्व मध्य	01	37
दक्षिण पूर्व	02	168
दक्षिण पश्चिम	01	18
दक्षिण	01	01
पश्चिम	03	65

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के बाद, परियोजना को आगे स्वीकृति प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों सहित विभिन्न हित-धारकों के साथ परामर्श और आवश्यक अनुमोदन यथा नीति आयोग का मूल्यांकन, वित्त मंत्रालय आदि की आवश्यकता होती है। चूंकि परियोजनाओं की स्वीकृति एक सतत् और गतिशील प्रक्रिया है, इसलिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

आंध्र प्रदेश में पूर्णत:/आंशिक रूप से पड़ने वाली नई लाइन परियोजनाएं भारतीय रेल के दक्षिण रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे और पूर्व तट रेलवे क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल हैं।

परियोजनाओं की लागत, व्यय, परिव्यय सहित क्षेत्रीय रेल-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाते हैं।

01.04.2024 तक, आंध्र प्रदेश में पूर्णत:/आंशिक रूप से पड़ने वाली 26,292 करोड़ रूपए की लागत वाली 1,935 किलोमीटर की कुल लंबाई को कवर करने वाली 17 नई लाइनें योजना/अनुमोदन/निष्पादन के चरण में हैं, जिनमें से 184 किलोमीटर लंबाई को चालू किया जा चुका है और मार्च 2024 तक 5,530 करोड़ रूपए का व्यय किया जा चुका है।

आंध्र प्रदेश राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाएं और संरक्षा कार्यों के लिए बजट आवंटन निम्नानुसार है:

वर्ष	बजट परिव्यय	2009-14 के औसत वार्षिक आबंटन की तुलना में वृद्धि
2009-14	886 करोड़ रूपए/प्रतिवर्ष	-
2024-25	9151 करोड़ रूपए	10 गुना से अधिक

आंध्र प्रदेश राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं की कमीशनिंग निम्नानुसार है:

अवधि	कमीशनिंग की गई कुल लंबाई	कमीशनिंग की गई औसत लंबाई	2009-14 के औसत आबंटन की तुलना में वृद्धि
2009-14	363 किमी.	72.6 किमी/ प्रतिवर्ष	-
2014-24	1510 किमी.	151 किमी/ प्रतिवर्ष	2 गुना से अधिक

रेल परियोजनाओं की शीघ्र मंजूरी और कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों में (i) गति शक्ति इकाइयों की स्थापना, (ii) परियोजनाओं की प्राथमिकता, (iii) प्राथमिकता वाली परियोजनाओं पर धन के आबंटन में पर्याप्त वृद्धि, (iv) क्षेत्रीय स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन, (v) विभिन्न स्तरों पर परियोजना की प्रगति की गहन निगरानी, और (vi) शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्यजीव संबंधी क्लीयरेंस और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों के समाधान के लिए राज्य सरकारों एवं संबंधित प्राधिकारियों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई शामिल है।

*****